

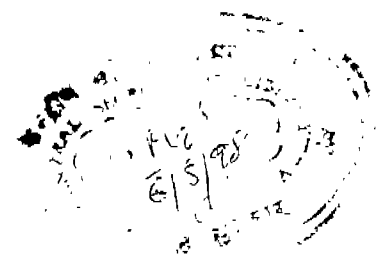
भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 98]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1998/ चैत्र 9, 1920

No. 98]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1998/CHAITRA 9, 1920

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1998

सा. का. नि. 151(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 267"

संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1998

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 1998 है।
2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।
3. (i) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 1997 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तंभ (2) से स्तंभ (8) में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियों, जो उक्त स्तंभों में उल्लिखित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्यक्रमों पर पूंजी की प्रकृति के व्यय के लिए हैं, भारत की संविधान निधि पर भारित होगी :—

सारणी

निम्नलिखित से संबंधित स्तर को ऊंचा उठाने के लिए

राज्य	अभिलेख क्रम	खजाने	शिक्षा	पुलिस	अग्निशमन	जेल	विशेष समस्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							(रुपए लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	118.130	..	45.000	46.230	731.250
अरुणाचल प्रदेश	91.550	1.230	562.500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
असम	53.830	25.875	1156.530	2027.920	47.500	58.430	..
बिहार	..	120.000	907.640	54.420	..	105.750	100.000
गोवा	0.650	..	0.900	15.300	47.500
हरियाणा	449.990
हिमाचल प्रदेश	27.900	20.000	306.630	186.020	36.250	8.920	1743.750
जम्मू-कश्मीर	11.030	277.330	..	5.740	..
कर्नाटक	191.250
केरल	533.750
मध्य प्रदेश	73.800	..	674.610
मणिपुर	6.180	1212.500
मेघालय	10.050	5.630	83.690	5.170	22.500	2.480	..
मिजोरम	1.300	7.130	..	72.760	23.750	5.700	4485.000
नागालैंड	..	4.500	..	407.720	..	7.200	880.750
उड़ीसा	94.620	51.020	95.000	43.230	911.250
पंजाब	18.030	15.750	41.010	713.130	150.000	32.400	..
राजस्थान	..	80.750	111.040	..	56.250	38.140	787.500
सिक्किम	6.710	16.870
तमिलनाडु	84.030	..
त्रिपुरा	2.850	6.000	88.040	257.670	30.000	9.600	285.000
उत्तर प्रदेश	..	375.000	90.000
पश्चिम बंगाल	116.410	26.130	..	577.390	190.000	..	1393.750

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां, ऊपर विनिर्दिष्ट और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तर को उठाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि किसी प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की रकम क्रमशः 1 अप्रैल, 1998 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के भीतर और 1 अप्रैल, 1999 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के भीतर, जैसा कि उन वर्षों के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऐसे प्रशासन से संबंधित अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर उपगत वास्तविक व्यय मदे समायोजन के अधीन रहते हुए है :

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां, अनुच्छेद 275 के खंड (1) के प्रत्येक उपबंध के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी।

के. आर. नारायणन्,
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 19(1)/98-वि.-1]

रघबीर सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1998

G.S.R. 151(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

“C.O.167”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1998

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered there commendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenue) Order, 1998.
2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.
3. (i) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1997, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (8) of the said Table, towards expenditure of capital nature, on programmes for upgradation of standards relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, namely:—

TABLE

For upgradation of standards relating to

State	Record Room	treasuries	Educational	Police	Fire Services	Jail	Special Problem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(Rupees in lakhs)							
Andhra Pradesh	118.130	..	45.000	46.230	731.250
Arunachal Pradesh	91.550	1.230	562.500
Assam	53.830	25.875	1156.530	2027.920	47.500	58.430	..
Bihar	..	120.000	907.640	54.420	..	105.750	100.000
Goa	0.650	..	0.900	15.300	47.500
Haryana	449.990
Himachal Pradesh	27.900	20.000	306.630	186.020	36.250	8.920	1743.750
Jammu and Kashmir	11.030	277.330	..	5.740	..
Karnataka	191.250
Kerala	533.750
Madhya Pradesh	73.800	..	674.610
Manipur	6.180	1212.500
Meghalaya	10.050	5.630	83.690	5.170	22.500	2.480	..
Mizoram	1.300	7.130	..	72.760	23.750	5.700	4485.000
Nagaland	..	4.500	..	407.720	..	7.200	880.750
Orissa	94.620	51.020	95.000	43.230	911.250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Punjab	18030	15,750	41,010	713.130	150.000	32.400	..
Rajasthan	..	80.750	111.040	..	56.250	38.140	787.500
Sikkim	6.710	16.870
Tamil Nadu	84.030	..
Tripura	2.850	6.000	88.040	257.670	30.000	9.600	285.000
Uttar Pradesh	..	375.000	90.000
West Bengal	116.410	26.130	..	577.390	190.000	..	1393.750

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgrading the standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by the Central Government:

Provided further that the amount of the grant specified above against any administration is subject to adjustment within the financial year commencing on the 1st day of April, 1998 and within the financial year commencing on the 1st day of April, 1999, respectively against the actual expenditure incurred on approved programme or programmes relating to such administration, as reflected in the accounts of those years.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

K.R. NARAYANAN,
President.

[F.No. 19(1)/98-L-I]
RAGHBIR SINGH, Secy.